

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	कार्तिक 9, शनिवार, शाके 1942- अक्टूबर 31, 2020 <i>Kartika 9, Saturday, Saka 1942- October 31, 2020</i>	

भाग 3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से
पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2020

संख्या एफ. 13(33)विशा/विस/2020:- सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No.33 of 2020

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2020

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Code of Civil Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, appoint.

2. Amendment of section 60, Central Act No. 5 of 1908.- In clause (b) of the proviso to sub-section (1) of the section 60 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), in its application to the State of Rajasthan, after the existing expression “judgment-debtor is an agriculturist,” and before the existing expression “his milch cattle”, the expression “his agricultural land to the extent of five acres,” shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The existing section 60 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) provides for the property liable to attachment and sale in execution of decree. Proviso to this section provides for certain particulars that shall not be liable to such attachment or sale.

In order to protect the interests and livelihood of agriculturists of the State it has been decided that if judgement-debtor is an agriculturist then his agricultural land to the extent of five acres shall not be liable to attachment or sale. Accordingly, section 60 of the Code of Civil Procedure, 1908 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

*A
Bill*

further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, in its application to the State of Rajasthan.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**Pramil kumar Mathur,
Secretary.**

2020 का विधेयक सं.33

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 1908 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 5 की धारा 60 का संशोधन.- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) को, राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, उसकी धारा 60 की उप-धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "कृषक है वहां" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "उसके दूध देने वाले" से पूर्व, अभिव्यक्ति "उसकी पांच एकड़ तक की कृषि भूमि," अंतःस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की विद्यमान धारा 60 ऐसी सम्पत्ति, जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, के लिए उपबंध करती है। इस धारा का परन्तुक कतिपय विशिष्ट वस्तुओं, जिन्हें ऐसे कुर्क या उनका विक्रय नहीं किया जा सकेगा, के लिए उपबंध करता है।

राज्य के कृषकों के हितों और उनकी आजीविका का संरक्षण करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि यदि निर्णीत-ऋणी कृषक है तो उसकी पांच एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क या उसका विक्रय नहीं किया जा सकेगा। तदनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।